

23 जिला कोर्ट जुड़े जिला अस्पतालों से, ई-समंस सेवा शुरू

बिलासपुर | हई कोर्ट की पहल पर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल की ओर बढ़ रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और बेमेतरा जिला अदालतों में डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य के सभी 23 जिला न्यायालयों को जिला अस्पतालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और आपराधिक मामलों में ई-समंस सेवा की भी शुरुआत की गई।

चीफ जस्टिस ने इस पहल को छत्तीसगढ़ न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि अब मेडिकल स्टाफ और गवाहों को कोर्ट में पेश होने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। वे सीधे अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दे सकेंगे। साथ ही ई-समंस की शुरुआत से समंस की सेवा प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी, जिससे न्याय वितरण में देरी नहीं होगी।



चीफ जस्टिस ने कहा कि वे लगातार जिलों का भ्रमण कर अधोसंरचना सुधार रहे हैं। अब न्यायालयों में फर्स्ट एड क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ अब ई-कोर्ट मिशन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। कार्यक्रम में हईकोर्ट कंप्यूटरीकरण समिति के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, अन्य न्यायाधीश, जिला जज, रजिस्ट्रार जनरल और न्यायिक अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बेमेतरा जिला न्यायालय के प्रधान जिला जज ने स्वागत भाषण दिया, समापन रायगढ़ जिला जज के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।